



तापमान 27 - 30
आर्द्रता 93%
सूर्योदय: 5:05 सूर्यास्त: 18:20

स्थानीय खबरें पृष्ठ दो, तीन, चार और पांच पर

कोलकाता, श्रावण शुक्लपक्ष द्वितीया, वि.स. 2082, पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

सुविचार : परम रहस्य केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनमें अपार धैर्य होता है।



विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा। यद् भद्रं तन्न आ सुवा।।

www.samagya.in

समाज्ञा



भारत-मालदीव संबंधों की जड़ें सागर जितनी गहरी: प्रधानमंत्री मोदी पृष्ठ 7

संसद में मानसून सत्र का पहला सप्ताह चढ़ा हंगामे की भेंट

अगले हफ्ते कामकाज होने के आसार



■ संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, एसआईआर लिखे

केंद्र की आपत्ति के बाद राज्यपाल ने अपराजिता विधेयक ममता सरकार को वापस भेजा

कोलकाता, समाज्ञा : राज्यपाल डॉ. सी वी आनंद बोस ने अपराजिता विधेयक को राज्य सरकार के पास विचार के लिए वापस भेज दिया है, क्योंकि केंद्र ने भारतीय न्याय संहिता में प्रस्तावित बदलावों को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई हैं। राजभवन के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने यह जानकारी दी। सूत्र ने कहा कि केंद्र ने अपने अवलोकन में पाया कि सितंबर 2024 में विधानसभा में पारित अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, बीएनएस की कई धाराओं के तहत दुष्कर्म के लिए सजा में बदलाव की मांग करता है, जो 'अत्यधिक कठोर और असंगत' हैं। बता दें कि विधेयक में दुष्कर्म के लिए सजा को बीएनएस

पोस्टर फाड़कर कूड़ेदान में डाले
■ स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष बोला- कोई नतीजा नहीं निकला

नयी दिल्ली : संसद के मानसून सत्र में शुक्रवार को भी विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित रही। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) समेत कई मुद्दों पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्यों ने शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित होने के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि राज्यसभा की बैठक भी 12 बजे के बाद स्थगित कर दी गई। हालांकि,

चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को बताया पारदर्शी

सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सहमति जताई है। सूत्रों के मुताबिक, 28 जुलाई को लोकसभा में इस मुद्दे पर बहस हो सकती है। हालांकि, बिहार वोट लिस्ट संशोधन पर सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि यह अभियान अवैध और डुप्लिकेट वोटों को हटाने के लिए जरूरी है। चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए कहा है कि इसका मकसद स्वच्छ मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। पक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में कई बार स्थान प्रस्ताव और नियम 267 के तहत नोटिस देकर इन मुद्दों पर चर्चा की मांग की है, लेकिन हंगामे के कारण दोनों सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित हो रही है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सप्ताह भर और विपक्ष की बैठक में यह सहमति बनी कि सोमवार से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाई जाएगी। कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश ने जानकारी दी कि अगले सप्ताह लोकसभा और राज्यसभा में पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा होगी। विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में एसआईआर वापस लो के नारे

लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर निराशा जताते हुए कहा कि यह व्यवधान नियोजित तरीके से किया जा रहा है और यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है। इस दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति आरक्षण से जुड़े एक विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

रोगियों को एटीएम मशीन समझने लगे हैं निजी अस्पताल: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोगियों के साथ एटीएम मशीन जैसा व्यवहार किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है और एक गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई के विरुद्ध चिकित्सक की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने कहा कि आजकल नर्सिंग होम और अस्पतालों में अपर्याप्त चिकित्सकों या बुनियादी ढांचे के बावजूद मरीजों को इलाज के लिए लुभाना आम बात हो गई है। अदालत ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं ने मरीजों से पैसे रकूँने के लिए उन्हें गिनी पिग/एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा, 35 लाख मतदाता पलायन कर गए या पता नहीं लगा : निर्वाचन आयोग

नयी दिल्ली : बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का पहला चरण शुक्रवार को समाप्त हो गया। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण की पहली चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बताया कि उसके स्थानीय चुनावी तंत्र ने रिपोर्ट दी है कि लगभग 35 लाख मतदाता या तो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या 24 जून के बाद से उनका पता नहीं चल सका है। इस वर्ष के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में राज्य में मतदाताओं की संख्या लगभग 7.90 करोड़ है। आयोग के मुताबिक, बृहत्-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) और राजनीतिक दलों के बृहत्-स्तरीय एजेंट (बीएलए) ने लगभग 22 लाख मतदाताओं के नामों की सूचना दी है। इसके अलावा, लगभग सात लाख मतदाता एक से ज्यादा स्थानों



पर पंजीकृत पाए गए। निर्वाचन आयोग ने बताया कि लगभग 1.2 लाख मतदाताओं के गणना फार्म अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। आयोग ने बताया कि अब तक बिहार के 99.8 प्रतिशत मतदाता इन प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं और 7.23 करोड़ मतदाताओं के प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें डिजिटल स्वरूप दिया जा चुका है। आयोग के मुताबिक, इन सभी 7.23 करोड़ मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। शेष मतदाताओं के प्रपत्रों और बीएलओ रिपोर्ट का डिजिटलीकरण भी एक अगस्त तक पूरा हो जाएगा।

बिकवाली दबाव में बाजार एक माह के निचले स्तर पर, सेंसेक्स 721 अंक फिसला

मुंबई : विदेशी पूंजी की लगातार निकासी के बीच वित्तीय, आईटी और तेल एवं गैस शेयरों में भारी बिकवाली होने से शुक्रवार को स्थानीय शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। सेंसेक्स 721 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी में 225 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 721.08 अंक यानी 0.88 प्रतिशत टूटकर एक महीने के निचले स्तर 81,463.09 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 786.48 अंक गिरकर 81,397.69 अंक पर आ

गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी भी बिकवाली के दबाव में 225.10 अंक यानी 0.90 प्रतिशत की गिरावट के साथ एक महीने के निचले स्तर 24,837 अंक पर आ गया। विश्लेषकों ने कहा कि एशियाई और यूरोपीय बाजारों में कमजोर रुख ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया।

विद्यार्थियों की आत्महत्या: युवाओं की लगातार जान जाना व्यवस्थागत विफलता को दर्शाता है : शीर्ष अदालत

शैक्षिक संस्थानों में आत्महत्याओं से निपटने के लिये शीर्ष अदालत ने देशव्यापी दिशानिर्देश जारी किए (पृष्ठ 7)

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि आत्महत्याओं के कारण युवाओं की लगातार जान जाना 'व्यवस्थागत विफलता' को दर्शाता है और इस मुद्दे को 'अनदेखा नहीं किया जा सकता'। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस मुद्दे से निपटने के लिए अखिल भारतीय स्तर

पर कई दिशानिर्देश पारित किए और कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा 2022 में 'भारत में आकस्मिक मौतों और आत्महत्याएं' शीर्षक से प्रकाशित आंकड़े 'बेहद चिंताजनक तस्वीर' पेश करते हैं। पीठ ने कहा, 'युवाओं की लगातार जा रही जान, जो अक्सर अनदेखे मनोवैज्ञानिक संकट, शैक्षिक बोझ, सामाजिक कलंक और संस्थागत अस्वेदनशीलता जैसे रोकें जा सकने वाले कारणों से होती है, एक प्रणालीगत विफलता को दर्शाती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।' भारत में 2022 में आत्महत्या के 1,70,924 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 7.6 प्रतिशत, यानी लगभग 13,044, विद्यार्थियों द्वारा की गई आत्महत्याएं थीं। पीठ

ने कहा कि उल्लेखनीय रूप से इनमें से 2,248 मौतें सीधे तौर पर परीक्षाओं में असफलता के कारण हुईं। एनसीआरबी के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि पिछले दो दशकों में विद्यार्थियों में आत्महत्या की संख्या बढ़ी है। वर्ष 2001 में 5,425 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की लेकिन यह आंकड़ा 2022 में बढ़कर 13,044 हो गया। पीठ ने कहा, 'स्कूलों, कॉलेज संस्थानों, कॉलेजों और प्रशिक्षण केंद्रों सहित शैक्षिक संस्थानों में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए, हम देश भर के शैक्षिक संस्थानों में छात्रों को प्रभावित कर रहे मानसिक स्वास्थ्य संकट की गंभीरता को स्वीकार करने और उसका समाधान करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं।'

पुरानी इमारतें बन रहीं खतरा, मेयर बोले- तुरंत गिराए जाएंगे मकान

7 नंबर बड़तल्ला स्ट्रीट की इमारत जल्द होगी ध्वस्त



कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता नगर निगम ने पुराने शहर क्षेत्रों में खतरनाक इमारतों को लेकर कड़ा रुख अमनाते हुए कहा है कि अब सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति नहीं की जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर ऐसी इमारतों को तुरंत ढहा दिया जाएगा। नगर निगम के मासिक अधिवेशन में मेयर फिरोज हकीम ने साफ शब्दों में कहा कि निगम अब और देर नहीं करेगा, क्योंकि यह जनता की जान का सवाल है।

वार्ड 22 की पार्श्व मीना देवी पुरोहित द्वारा बड़ाबाजार इलाके के 7 नंबर बड़तल्ला स्ट्रीट स्थित सात अति जरूरत मकानों का मुद्दा उठाए जाने के बाद मेयर ने आश्वासन दिया कि इन भवनों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन इमारतों

की हालत इतनी खराब है कि किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना हो सकती है और निगम अब हादसे का इंतजार नहीं करेगा। मेयर ने यह भी माना कि कई बार निगम की कार्रवाई कोर्ट के स्ट्रे ऑर्डर या कानूनी पेचों में अटक जाती है। लेकिन इस बार निगम पुलिस और कानूनी विशेषज्ञों की मदद लेकर ऐसे अवरोधों को पार करेगा। उन्होंने कहा, जहां भी जरूरी होगा, पुलिस की मौजूदगी में हम खुद भवन गिराएंगे।

अधिवेशन में पार्श्व ने बताया कि कई खतरनाक इमारतों में अभी भी

लोग रह रहे हैं और व्यापारिक गतिविधियां भी जारी हैं, जिससे न सिर्फ वहां रहने वालों, बल्कि आसपास के लोगों की जान को भी खतरा है। मेयर ने पार्श्व की बात से सहमति जताते हुए भरोसा दिया कि अब निगम ऐसे मामलों में त्वरित और ठोस कदम उठाएगा। नगर निगम ने पुराने क्षेत्रों जैसे बड़ाबाजार, बहुबाजार, सेंट्रल एवेन्यू और प्लेस्टा में स्थित जरूरत इमारतों की नई सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में इन इमारतों को नोटिस भेजे जाएंगे। अगर मकान मालिक समय पर मरम्मत नहीं करते या भवन खाली नहीं करते, तो निगम सीधे तौर पर भवन को गिराने की कार्रवाई करेगा।

मेयर हकीम ने अंत में कहा, हमारी प्राथमिकता है शहरवासियों की सुरक्षा। यदि कोई भवन जान के लिए खतरा बन चुका है, तो हम किसी भी हालत में कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे।

गेमिंग ऐप में चैट सुविधा का इस्तेमाल आतंकवादी समूह आपस में संवाद के लिए कर रहे : अधिकारी

श्रीनगर : पबजी जैसे ऑनलाइन खेल में गुमनाम या अन्य साधियों के साथ बातचीत में आवश्यकता होती है और अब इन खेलों की यही विशेषता आतंकवादी समूहों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के

लिए जम्मू-कश्मीर में अपने सदस्यों से संवाद करने के प्रमुख संचार माध्यम में बदल गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक, सीमा पर सक्रिय आतंकवादी समूह सोशल मीडिया और संचार के

पारंपरिक माध्यमों को दरकिनार कर सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से बचने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे इस आभासी युद्धक्षेत्र को असली में युद्ध के संवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे चार मामलों की पहचान की गई है।

ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी, सेना को बहुत उच्च स्तर की तैयारी रखनी चाहिए: सीडीएस



नयी दिल्ली : प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और देश को चौबीस घंटे व पूरे वर्ष बहुत उच्च स्तर की सैन्य तैयारी रखनी चाहिए। यहां सुब्रतो पार्क में आयोजित रक्षा संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में सेना को सूचना योद्धा-1ओं, प्रौद्योगिकी योद्धाओं और विद्वान योद्धाओं की भी जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि युद्ध के इस परिदृश्य में, भावी सैनिकों को सूचना, प्रौद्योगिकी

राज्यसभा महासचिव को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया

नयी दिल्ली : भारत के 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए कदम आगे बढ़ते हुए निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राज्यसभा के महासचिव पी सी मोदी को चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। जगदीप धनखड़ ने सोमवार शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था जिसके कारण यह चुनाव कराना आवश्यक हो गया है। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होना था। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा कि कानून एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श करने और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति के बाद उसने 2025 के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पी सी मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने दिखाया कि 50 से कम हथियार शत्रु को वार्ता की मेज पर ला सकते हैं : वायुसेना उपप्रमुख भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदहर तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' ने यह दिखा दिया है कि केसे 50 से भी कम हथियारों से दुश्मन को बातचीत की मेज पर लाया जा सकता है। उन्होंने इसे एक ऐसा उदाहरण बताया जिसका अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह बात विचारक संस्था 'सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज' (सीएपीएस) और 'कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर' द्वारा आयोजित एक सम्मेलन के संवाद सत्र के दौरान कही। तिवारी ने कहा, "हमने लाभ-हानि, खासकर हवाई शक्ति के बारे में काफी चर्चा की। मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है... जैसा हमने 'ऑपरेशन सिंदूर' में किया।"

ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि 50 से कम हथियार शत्रु को वार्ता की मेज पर ला सकते हैं : वायुसेना उपप्रमुख

कोलकाता, समाज्ञा : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़े पैमाने पर हुए चिटफंड घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य कंवर दीप सिंह से जुड़ी संस्थाओं के स्वामित्व वाले दो अस्पतालों के 127.33 करोड़ रुपये के शेयर कुर्क किए हैं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पंचकूला स्थित अलकेमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल के शेयरों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों का स्वामित्व केडी सिंह के बेटे करण दीप सिंह के पास है। यह कार्रवाई अलकेमिस्ट समूह, उसके निदेशकों, प्रमोटर्स और संबंधित संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोपों की चल रही जांच का हिस्सा है। ईडी के अनुसार, एकत्र किए गए धन को समूह की कंपनियों के बीच जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से उनके सह-खरीदने और अलकेमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल बनाने के लिए किया गया। ईडी का कहना है कि फिर अपराध की आय को छिपाने के लिए वैध संपत्ति के रूप में पेश किया गया था। जांच में पाया गया कि मेसर्स सौर एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी जो करण दीप सिंह के लाभकारी स्वामित्व में है, के पास अलकेमिस्ट अस्पताल में 40.94 प्रतिशत शेयर और ओजस अस्पताल में 37.24 प्रतिशत शेयर हैं। अब तक, ईडी ने इस मामले में पांच अलग-अलग आदेशों के माध्यम से 238.42 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।



Assure
Moving the world together.

A PRODUCT OF CHHAJER GROUP

MIXER GRINDER

PRINCE
POWERFUL 750W MOTOR
100% COPPER BLEND

CHAMPION
POWERFUL 850W MOTOR
100% COPPER BLEND

PRESSURE COOKER
CLASSIC AVAILABLE SIZE: 1.5L / 2L / 3L / 5L / 6.5L / 8L / 10L

NONSTICK COOKWARE
DURACOAT
PFOA FREE
2 YEARS WARRANTY

STAINLESS STEEL BOTTLE
750 & 1000 ML

TOWER FAN
BREEZE MASTER
150 WATTS
1 YEAR WARRANTY

APPLIANCES RANGE: MIXER GRINDER, ELECTRIC KETTLE, NONSTICK COOKWARE, INDUCTION, IRON, SANDWICH MAKER & POP UP TOASTER, PRESSURE COOKER, SS BOTTLE & FLASK, FAN ETC.

AVAILABLE AT ALL LEADING STORE

FOR BULK BOOKING & CORPORATE ENQUIRY SOLICITED

81004 68652 / 98745 51349 / 033 22254452

Website: www.assure-india.com E-mail: assuredc@gmail.com

कोलकाता नगर निगम में अब सिर्फ बंगला में होगी बहस, अध्यक्ष ने दी स्पष्ट निर्देश

कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बंगला भाषा के सम्मान और संरक्षण को लेकर दिए गए 'भाषा आंदोलन' के आह्वान के बीच, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने एक अहम फैसला लिया है। नगर निगम की अध्यक्ष माला राय ने घोषणा की है कि अब से निगम की किसी भी बैठक या सत्र में पार्षद केवल बंगला भाषा में ही सवाल पूछ सकेंगे। हिंदी या अंग्रेजी में सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माला राय ने कहा कि यह फैसला बंगला

भाषा को प्राथमिकता देने और उसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। उनका कहना है कि नगर निगम की बैठकों में अधिकांश सवाल पहले से ही बंगला में पूछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ पार्षद अब भी हिंदी या अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। अब से सभी को बंगला में ही संवाद करना होगा और नगर प्रशासन के सदस्य भी उसी भाषा में उत्तर देंगे। इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं कि गैर-बंगाली पार्षदों का क्या होगा? इस पर माला राय ने कहा कि जो लोग



लंबे समय से बंगाल में रह रहे हैं, वे बंगला समझते और बोलते हैं। इसलिए भाषा को लेकर कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने

यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ स्टाइल दिखाने के लिए अंग्रेजी बोलने की प्रवृत्ति अब बंद नहीं की जाएगी। जब अधिवेशन बंगाल में हो रहा है, तो वहां पहली भाषा बंगला ही होनी चाहिए। इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भाजपा पार्षद सज्जद घोष ने इस निर्णय को तृणमूल सरकार का ढोंग बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार ने आठ हजार बंगला भाषी पार्षदों को हटा दिया और बीस हजार बंगला शराब की दुकानें

खोलीं। अब दिखावे के लिए बंगला भाषा को सर्वोच्च स्थान देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी तर्क कसा कि अगर सचमुच भाषा आंदोलन को महत्व दिया जा रहा है, तो दारिद्र्य में मारे गए दो युवकों की प्रतिमा लगाई जाए, जो 2018 में भाषा आंदोलन के नाम पर जान गंवा बैठे थे। कोलकाता नगर निगम का यह फैसला भाषा को लेकर एक नई बहस की शुरुआत कर चुका है, जो भविष्य में राज्य की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है।

कोलकाता के विरासत भवनों की रक्षा के लिए आंगा क्यूआर कोड और टूरिस्ट गाइडबुक

कोलकाता : शहर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित और लोकप्रिय बनाने के लिए कोलकाता नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। विरासत भवनों की सूची, खरखार और पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर नगर निगम के 48 नंबर वार्ड के पार्षद विधुकर दे ने हाल ही में नगर निगम में एक अहम सवाल उठाया। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि नगर निगम के अंतर्गत आने वाले हेरिटेज-1 श्रेणी के भवनों की जानकारी के साथ एक टूरिस्ट गाइडबुक प्रकाशित की जाए, जिससे कोलकाता को लेकर पर्यटकों की रुचि और बढ़ेगी। इस प्रस्ताव का जवाब देते हुए पर्यावरण और विरासत मामलों के मेयर परिषद सदस्य स्वप्न समार ने कहा, शहर

में फिलहाल कुल 1,392 विरासत भवन हैं, जिनमें से 717 भवन हेरिटेज-1 श्रेणी में आते हैं। इन भवनों के सामने 'ब्लू प्लैग' लगाने का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब हर विरासत भवन के सामने एक क्यूआर कोड भी लगाया जाएगा। इस कोड को स्कैन करने पर उस भवन का इतिहास, स्थापत्य शैली और अन्य रोचक जानकारियाँ तुरंत मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देंगी। स्वप्न समार ने कहा, यह पहल छात्रों से लेकर पर्यटकों तक, सभी के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक होगी। कोलकाता नगर निगम की यह आधुनिक पहल न सिर्फ विरासत के संरक्षण में मदद करेगी, बल्कि पर्यटन को भी नई दिशा देगी।

नाम परिवर्तन
में रमेश चन्द्र सिंह, पुत्र- बाके सिंह, निवासी गाँव- सिसवन, डाकघर- गंगपुर सिसवन, जिला- सिसवन, (बिहार), पिन- 841210 घोषणा करता हूँ कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, छपरा कोर्ट के समक्ष दिनांक 21.07.2025 को दिए गए शपथ पत्र के माध्यम से मैंने अपना नाम बदलकर रमेश सिंह कर लिया है। जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र के अनुसूच है। रमेश चन्द्र सिंह और रमेश सिंह एक ही व्यक्ति हैं। अतः अब से मेरा सही नाम रमेश सिंह, पिता- बाके सिंह ही पढ़ा और इस्तेमाल किया जाए।

NAME CHANGE

I, Sunita Chowdhary, wife of Gopal Chowdhary, daughter of Kirodi Mal Agarwal, residing at 493/C/A, Phase-1, Block-D, 3rd floor, Vivek Vihar, G T Road, Shibpur, Howrah-711102, do hereby solemnly affirm and declare that Sunita Chowdhary and Sunita Agarwal Chowdhary (maiden name) both are the name of one and same identical person indicating myself via affidavit before the Notary Public at Howrah dated 23rd June 2025.

कोलकाता में जलजमाव को लेकर मेयर फिरहाद हकीम का बीजेपी पर तीखा हमला

कोलकाता, समाज्ञा : कोलकाता में लगातार बारिश के कारण जलजमाव की स्थिति पर शुक्रवार को कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने एक संवाददाता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी तस्वीरें खींचकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जबकि नगर निगम जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। हकीम ने कहा, कोलकाता में पांच घंटे से ज्यादा पानी कहीं जमा नहीं रहता। सूत और दिढ़ी जैसे शहरों में पांच-पांच दिन पानी भरा रहता है। लेकिन बीजेपी सिर्फ तस्वीरें दिखाकर प्रचार कर रही है।

मेयर ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से इस समस्या से निपटने के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती, जबकि विपंग स्टेशन बनाने में

भारी लागत आती है। उन्होंने कहा, हम जादू नहीं जानते, लेकिन सीमित संसाधनों में अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। इस बार पटिपुकुर अंडरपास में पानी नहीं भरा - यह हमारी व्यवस्था का ही परिणाम है। फिरहाद हकीम ने बताया कि जहां-जहां बार-बार जलजमाव होता है, वहां पेंवर ब्लॉक लगाने का निर्णय लिया गया है। जैसे ही किसी इलाके में सूखी जमीन दिखती है, वहां तुरंत मरम्मत कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि तारातला, गरगाछा और बंदर जैसे क्षेत्रों में जलनिकासी की व्यवस्था नहीं है और इसके समाधान के लिए पोर्ट ट्रस्ट को पत्र भेजा गया है। हकीम ने दो ट्रक कहा कि जनता केवल तस्वीरों से रूक, काम से प्रभावित होती है, और कोलकाता नगर निगम की प्राथमिकता केवल प्रचार नहीं, बल्कि समाधान है।

युवा आयोग का बड़ा फैसला: बूथ लेवल अधिकारियों को मिलेगा प्रतिरिक्त भत्ता

कोलकाता : राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के लिए एक अहम घोषणा की है। अब अगर वे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण या आयोग द्वारा निर्देशित कोई विशेष कार्यक्रम करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2,000 रुपये का विशेष भत्ता दिया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र भेजकर जानकारी दी है। इस फैसले के तहत बूथ लेवल अधिकारियों के वार्षिक भत्ते को लगभग दोगुना कर दिया गया है। अब बीएलओ को 12,000 रुपये वार्षिक भत्ता मिलेगा। वहीं, जो बीएलओ सुपरवाइजर की भूमिका निभाएंगे, उन्हें अब 18,000 रुपये सालाना भत्ता मिलेगा। यह निर्णय बीएलओ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने और उनके काम की महत्ता को स्वीकार करने के उद्देश्य से लिया गया है।

एसआईआर मुद्दे पर संसद में चर्चा तृणमूल कांग्रेस की सर्वोच्च प्राथमिकता : डेरेक ओ ब्रायन

नयी दिल्ली/कोलकाता : कोलकाता कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने शुक्रवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर संसद में चर्चा कराना पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता ओ ब्रायन ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सदन चले। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा से भाग रही है। उन्होंने यह दावा भी किया कि एसआईआर अगले साल पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी किया जाना है। डेरेक ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों से बात कर रही है और निर्वाचन सदन का 'घेराव' करने पर विचार कर सकती है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि



एसआईआर मुद्दा संसद में चर्चा के लिए तृणमूल कांग्रेस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव करने का अधिकार है, लेकिन हम वास्तविक नागरिकों, यानी मतदाताओं, को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की इजाजत नहीं दे सकते। विपक्षी दल एकजुट हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। एसआईआर मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि

आप, लोगों को मतदाता सूची से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यह पूरी तरह से हस्तक्षेप और जबरदस्त धोखाधड़ी है। डेरेक ने कहा कि विपक्षी दल संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे और निर्वाचन आयोग के कार्यालय (निर्वाचन सदन) का घेराव करने के विकल्प पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम समान विचारधारा वाले दलों से इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें निर्वाचन सदन का घेराव करना चाहिए। तृणमूल नेता ने निर्वाचन आयोग पर 'भाजपा के शाखा कार्यालय' की तरह काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा के शाखा कार्यालय की तरह काम कर रहा है। वे लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। यह केवल बिहार के लिए नहीं है। यह पूरे देश में एक

तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र पर बंगाल विरोधी होने का आरोप लगाया

तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्र पर बंगाल विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि राज्यसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से जुड़े एक सवाल के लिखित जवाब में पश्चिम बंगाल का नाम नहीं था। राज्यसभा में तृणमूल नेता डेरेक ओ ब्रायन के एक सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी, जिसमें पश्चिम बंगाल का नाम नहीं था। तृणमूल के राज्यसभा सदस्य रीताबत्रा बनर्जी ने कहा कि डेरेक ओ ब्रायन ने मनरेगा के बारे में एक सवाल किया था। जवाब में पश्चिम बंगाल का नाम न होना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की बांग्ला-विरोधी मानसिकता स्पष्ट है। यहां तक कि संसद में दिए गए जवाबों में भी पश्चिम बंगाल का नाम नहीं है। ओ ब्रायन ने अपने प्रश्न के जरिये यह जानना चाहा था कि क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बीच मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवारों की संख्या में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि प्रति परिवार औसत रोजगार के दिनों में गिरावट आई है।

खतरनाक चाल है। तृणमूल नेता ने सवाल किया कि आयोग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की आड़ में बंगाल से 1,000 बीएलओ (बूथ स्तर के अधिकारियों) क्यों बुलाए हैं? उनके पास क्या कुटिल योजनाएँ हैं? उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष चाहता है कि संसद की कार्यवाही चले और

एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि संसद की कार्यवाही चले, हर विपक्षी दल चाहता है कि संसद की कार्यवाही चले। तृणमूल कांग्रेस संसद ने कहा कि हम एसआईआर पर किसी भी नियम के तहत चर्चा

चाहते हैं। अगर सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है, तो इसका मतलब है कि वे सदन में व्यवधान डालना चाहते हैं।

सीईओ कार्यालय में तीन रिक्त पदों पर नियुक्ति की तैयारी, नबान्ना ने भेजे तीन नामों के पैनाल

कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब एक वर्ष से भी कम का समय शेष है, ऐसे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। नबान्ना (राज्य सचिवालय) ने अतिरिक्त सीईओ, संयुक्त सीईओ और डिप्टी सीईओ पदों के लिए तीन अलग-अलग पैनाल चुनाव आयोग को भेज दिए हैं।



सूत्रों के अनुसार, इन तीन महत्वपूर्ण पदों पर लंबे समय से नियुक्ति नहीं हुई थी। आगामी चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए नबान्ना ने इन पदों को जल्द भरने की सिफारिश की है। आयोग की मंजूरी मिलते ही अंतिम नियुक्तियों की घोषणा की जाएगी। अतिरिक्त सीईओ पद के लिए

प्रस्तावित नाम हैं:
□ सुदीप मित्रा, स्पेशल सेक्रेटरी (प्रशासनिक कार्यदाता)
□ सुजाय सरकार, स्पेशल सेक्रेटरी (विधाननगर नगर निगम)
□ सुदीप सरकार, एडिशनल सेक्रेटरी (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)
संयुक्त सीईओ पद के लिए
□ रंजन चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव (विद्युत विभाग)
□ प्रियंजन दास, संयुक्त सचिव (लोक निर्माण विभाग)
□ राजीव मंडल, लैंड मैनेजर (विधाननगर शहरी विकास एवं नगर मामलों का विभाग)
इन नियुक्तियों से चुनाव आयोग की तैयारियों को नया बल मिलने की उम्मीद है।

बुबाजार में पुरानी इमारत का बड़ा हिस्सा ढहा, कोई हताहत नहीं

स्थानीय तृणमूल पार्षद ने की असुरक्षित इमारत को गिराने की मांग

कोलकाता, समाज्ञा : रात भर हुई बारिश के बीच मध्य कोलकाता के बुबाजार स्थित एक निजी मार्केट की बहुत पुरानी इमारत का एक हिस्सा शुक्रवार के तड़के ढह गया। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस के अनुसार, यह घटना सुबह लगभग 5 बजे घटी, जब इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढहकर सड़क पर गिर गया। बारिश के कारण, मार्केट के बाहर फुटपाथ पर सोने वाले कुछ मजदूर इमारत के अंदर थे और बाल-बाल बच गए। वार्ड 48 के स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पार्षद विश्वरूप दे ने कहा कि उन्होंने कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम के समक्ष असुरक्षित घोषित की गई इस इमारत का मुद्दा उठाया था। उन्होंने मेयर से मांग की कि इस मार्केट को बंद कर जर्जर हो



चुकी इस पुरानी इमारत को गिरा दिया जाना चाहिए और दुकानदारों और मजदूरों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पार्षद ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि शुक्र है कि आज कोई हताहत नहीं हुआ। यह एक बड़ी आपदा थी। बताया जा रहा है कि कोलकाता नगर निगम ने इस मार्केट के दुकानदारों से इमारत खाली करने के लिए कई बार बातचीत की,

लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। पार्षद ने आगे कहा कि अगर इस इमारत को खाली नहीं किया गया या गिराया नहीं गया, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस जर्जर इमारत को गिराना ही एकमात्र रास्ता है। इमारत की मरम्मत नहीं की जा सकती। उन्होंने इसके लिए दुकानदारों से भी सहयोग की अपील की ताकि भविष्य में कोई जान-माल का नुकसान न हो।

रोज वैली मामले की जांच पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सीबीआई से मांगी प्राथमिक रिपोर्ट

कोलकाता : रोज वैली चिटफंड घोटाले की जांच की धीमी गति और अनियमितताओं को लेकर शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जहिर की। न्यायमूर्ति राजर्षि भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति ऋतब्रत मित्र की खंडपीठ ने जांच एजेंसियों की रिपोर्टों और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद सीबीआई की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस समाह के भीतर रोज वैली से संबंधित सभी दस्तावेज ईडी और सीबीआई को सौंपे जाएं, और आगामी शुक्रवार को कोर्ट में पेश होकर सीबीआई को 15 दिनों के भीतर प्राथमिक जांच रिपोर्ट जमा करनी होगी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रोज वैली में करीब 31 लाख आवेदन दाखिल हुए हैं और

इस कंपनी ने लगभग एक करोड़ लोगों से पैसे जुटाए हैं। फिलहाल लगभग 74 हजार निवेशकों को पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जबकि एजेंसियों के पास अभी भी 531 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए पूछा, जब इतना पैसा है, फिर अब तक भुगतान क्यों नहीं हुआ? और कितना वक्त लगेगा? कम से कम 30 प्रतिशत निवेशकों को तो पैसा लौटाइए। जज ने आगे कहा कि रोज वैली की जो जल्द संपत्तियाँ हैं, उन्हें अब तक बेचा नहीं गया है, बल्कि उन संपत्तियों से दो लोगों को जोड़कर होटल का व्यवसाय चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी ने ही उन्हें यह अवसर दिया, जबकि वे दोनों लोग रोज वैली की किसी भी सहयोगी कंपनी के निदेशक नहीं थे। कोर्ट ने सवाल किया कि जब इन



लोगों को कोर्ट ने नियुक्त नहीं किया, तो ईडी ने किस अधिकार से इन्हें जोड़ा? एडीसी कमिटी ने जवाब में कहा कि ईडी ने ही इन दोनों को जोड़ने को कहा था। इस पर कोर्ट ने थोड़ा ईडी को किससे अधिकार दिया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को इयॉम शामिल करें? किस कानून या कोर्ट के आदेश से वे किया गया? ईडी ने जवाब में कहा कि उन्होंने केवल

निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया, और उनका कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। मगर कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। जज ने दो ट्रक कहा, बहुत अच्छा, लेकिन ईडी को ये अधिकार किसने दिया? अगर मुझे संपत्तियों के अंदर थे और बाबल-बाल बच गए। वार्ड 48 के स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पार्षद विश्वरूप दे ने कहा कि उन्होंने कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम के समक्ष असुरक्षित घोषित की गई इस इमारत का मुद्दा उठाया था। उन्होंने मेयर से मांग की कि इस मार्केट को बंद कर जर्जर हो

पूछा कि एडीसी कमिटी ने चॉकलेट ग्रुप नाम की कंपनी को होटल चलाने की अनुमति कैसे दी और वह दो लोग इससे कैसे जुड़े? कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब जमाकर्ताओं के प्रतिनिधि भी इस कमिटी में शामिल थे, तब उन्होंने इन अनियमितताओं का विरोध क्यों नहीं किया? जवाब में एक वकील ने कहा कि उन्हें केवल जल्द संपत्तियों की गिनतारी के लिए एक उप-समिति में रखा गया था और उन्हें मुख्य कमिटी की बैठकों में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था। इस पर न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि कोर्ट खुद जांच नहीं कर सकता, यह जिम्मा जांच एजेंसियों का है और इसलिए सीबीआई को इस मामले में कदम उठाना होगा।

www.samagya.in

समाचा

NEWS PAPER ADVERTISING SOLUTION

- MATRIMONIAL
- EDUCATION
- OBITUARY
- PROPERTY
- NAME CHANGE
- REMEMBRANCE
- RECRUITMENT
- PUBLIC NOTICE
- DISPLAY

TO AD IN SAMAGYA PLEASE CONTACT

samagyaadvt@gmail.com | samagya.in

81, Chintamani Dey Road, Howrah 711 101, Mobile: 70444 44522

आलू की कीमतों में गिरावट से किसानों, भंडारण इकाइयों का संकट बढ़ा : बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन

कोलकाता, समाज्ञ : पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन (डब्ल्यूबीसीएसए) ने शुक्रवार को थोक आलू की कीमतों में भारी गिरावट पर चिंता जताई और किसानों एवं 'कोल्ड स्टोरेज' संचालकों को भारी वित्तीय नुकसान होने के बारे में आगाह किया। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में गहराते आर्थिक संकट को रोकने के लिए तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की मांग की। डब्ल्यूबीसीएसए के अध्यक्ष सुनील कुमार राणा ने कहा कि थोक और खुदरा कीमतों के बीच बढ़ता अंतर किसानों पर भारी दबाव डाल रहा है, जिनके पास इस साल लगभग 80 प्रतिशत आलू का भंडार है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि आलू की खेती और भंडारण का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है। इस साल, राज्य के कोल्ड स्टोरेज में रिकॉर्ड



70.85 लाख मीट्रिक टन आलू रखा हुआ है, जिसमें पिछले मौसम में अंतर-राज्यीय आव-जाही पर प्रतिबंध के कारण 10 लाख टन अतिरिक्त अंग्रेजी किस्म का आलू भी शामिल है। अधिकांश भंडारण इकाइयां अब पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। संघ के उपाध्यक्ष सुभाजीत साहा ने कहा कि ज्योति किस्म का थोक मूल्य, जो मई में उतराई की शुरुआत के दौरान

राज्य द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 15 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था, अब गिरकर नौ रुपये प्रति किलोग्राम रह गया है। साहा ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार 15 रुपये प्रति किलोग्राम का थोक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था चमत्कार जाएगी और किसान अगले साल बुवाई से हतोत्साहित होंगे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने किसानों से 11 लाख टन (या 2.2 करोड़ बैकेट) आलू खरीदने का अपना मार्च का वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। डब्ल्यूबीसीएसए ने राज्य से कुछ सुधारात्मक उपाय करने का आग्रह किया, जिन्हें एमएसपी पर तत्काल खरीद, अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय आलू व्यापार को

बढ़ावा देना और मध्यह्रद भोजन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं में आलू को शामिल करना शामिल है। इसने राज्य के बाहर स्टॉक की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए परिवहन सब्सिडी शुरू करने की भी सिफारिश की। राणा ने कहा कि अगर ये कदम तुरंत नहीं उठाए गए, तो मांग-आपूर्ति में असंतुलन पैदा होगा, बुवाई कम होगी, शीतगृहों का कम उपयोग होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है। संघ ने चेतावनी दी कि ठोस नीतिगत समर्थन के बिना, राज्य की 10,000 करोड़ रुपये की आलू अर्थव्यवस्था को व्यापक संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर किसानों, भंडारण इकाइयों और व्यापक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

आसनसोल में सड़क दुर्घटना में दो बाइक सवारों की मौत

आसनसोल : आसनसोल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर एक सड़क दुर्घटना में दो बाइक सवारों की मौत हो गई। दुर्घटना के कारण यातायात बाधित हो गया। आसनसोल दक्षिण थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, आसनसोल से दुर्गापुर जाते समय काली पहाड़ी चौराहे पर एक चार पहिया वाहन की चपेट में आने से दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। दुर्घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने हत्यारे वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

बड़ाबाजार में तांत्रिक वस्तुओं को बेचने की आड़ में वन्यजीव अंगों की तस्करी, दो गिरफ्तार

कोलकाता, समाज्ञ : कोलकाता में तांत्रिक वस्तुओं को बेचने की आड़ में वन्यजीव अंगों की तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। वन्यजीव अपराध ब्यूरो (वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो) ने खरीदार की आड़ में वन्यजीव अंगों की तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बड़ाबाजार से दो विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया। जंगली सूअर के दाँत, साँप का लिंग और समुद्री सूअर सी फेन जब्त किया गया है। गिरफ्तार लोगों के नाम बिदेश्वरी साव और मोहन गुप्ता हैं। बता दें कि तांत्रिक इस सी फेन का उपयोग काला जादू करने के लिए करते हैं। जिसका बाजार मूल्य लाखों रुपये से अधिक है। बड़ाबाजार चौक



में एक बहुत पुरानी दुकान है। इसे सामने से देखने पर यह एक जौहरी की दुकान जैसी दिखती है। स्वाभाविक रूप से, किसी को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। वन्यजीव अपराध ब्यूरो को एक विशेष स्रोत से सूचना मिली कि एक जौहरी की दुकान की आड़ में वन्यजीव अंगों की तस्करी चल रही थी वे मंगलवार को वहां गए और विक्रेताओं से मोलभाव किया। उन्हें बताया गया

कि वे अगले दिन दुकान पर आकर उन्हें ले जाएंगे। अधिकारियों ने कुछ अग्रिम राशि भी दी ताकि विक्रेताओं को शक न हो। बुधवार की दोपहर को नियत समय पर दोनों अधिकारी फिर दुकान पर पहुंचे। टीम के बाकी सदस्य बाहर इंतजार कर रहे थे। विक्रेता उन्हें खरीदार को सौंपने ही वाला था कि वे पकड़े गए। जब्त की गई वस्तुओं में 60 गाय के साँप के लिंग, 10 जंगली सूअर के दाँत और 250 समुद्री सूअर शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस गिरोह के पीछे एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हाथ है। ये कहां से लाए जा रहे थे? इनकी आपूर्ति कौन कर रहा है? वन विभाग गिरफ्तार लोगों से पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश कर रहा है।

बनगांव में बंद घर से कारोबारी का सड़ा-गला शव बरामद

कोलकाता, समाज्ञ : उत्तर 24 परगना जिला के बनगांव थाना अंतर्गत गोबरापुर इलाके में एक बंद घर से कारोबारी का सूखता सड़ा-गला शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान आनंद विश्वास (54) के रूप में की गई है। उनका गांडापोता बाजार में पान का व्यवसाय है। पुलिस और परिवार का प्रारंभिक अनुमान है कि व्यवसायी ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से इलाके में काफी हड़कंध मच गया है। परिवार और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, आनंद विश्वास शनिवार को अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक रिश्तेदार के घर गए थे। आनंद विश्वास उन्हें वहीं छोड़कर घर लौट आए। हालांकि, किसी को नहीं पता कि वह घर कब लौटे। हालांकि, उनसे फोन पर संपर्क करने की कई कोशिश की गई, लेकिन उनके

रिश्तेदारों का फोन से संपर्क नहीं हो सका। गुरुवार की दोपहर को, उनके भाई के परिवार के सदस्यों को बंद घर से दुग्ध आई और मस्खियां भिन्नभिन्न दिखीं। फिर, उन्होंने पंचायत सदस्यों और गांडापोता पुलिस चौकी को सूचित किया, पुलिस ने आकर बंद घर का दरवाजा तोड़ा, आनंद विश्वास का शव बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए बनगांव अस्पताल भेज दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, आनंद की बेटी की शादी अगामी फाल्गुण माह में होने वाली है और वह कुछ कर्ज में डूबे हुए हैं। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि बेटी की शादी और कर्ज की चिंता के कारण आनंद ने आत्महत्या की होगी। हालांकि, बनगांव पुलिस ने अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।

भागलपुर और दानापुर के बीच श्रावणी मेले के लिए चलैगी स्पेशल ट्रेन

कोलकाता, समाज्ञ : श्रावणी मेला के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर और दानापुर के बीच अतिरिक्त श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। दानापुर से भागलपुर के लिए 03234 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन 25, 26 और 27 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन रात 10:00 बजे भागलपुर पहुंचेगी। वहीं, 03233 भागलपुर-दानापुर स्पेशल ट्रेन 26, 27 और 28 जुलाई को रात 1:00 बजे भागलपुर से रवाना होकर सुबह 7:50 बजे दानापुर पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन पूर्व रेलवे के सुल्तानगंज, जमालपुर और अरुणपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रुकेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें सामान्य द्वितीय श्रेणी और स्लीपर श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे।

बैंडेल में बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध मार्च, पुलिस से झड़प, चार कार्यकर्ता हिरासत में

हुगली : बैंडेल में शुक्रवार को बीजेपी युवा मोर्चा ने कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और कार्यकर्ताओं पर हमलों के विरोध में रैली निकाली। यह मार्च कैंटिन बाजार मोड़ से शुरू होकर बैंडेल फाड़ी तक गया, जहां 5 सूत्रीय मांगों को लेकर स्मारक पत्र सौंपा जाना था। मार्च का नेतृत्व भाजपा के युवा नेता राजीव घनुमी कर रहे थे। पुलिस को पहले ही सूचना दी गई थी, लेकिन फाड़ी के पास पहुंचते ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च को रोकने की कोशिश की। इस पर पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की हुई। स्थिति तब उग्र हो गई जब महिला कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर थाना परिसर तक पहुंच बना ली। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने फाड़ी के ओसी को मांगत्र सौंपा। मौके पर जिला भाजपा नेता सुरेश साव, गोपाल उपाध्याय सहित कई नेता मौजूद थे। घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस ने दो महिला और दो पुरुष भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके घर से हिरासत में ले लिया। भाजपा ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और जल्द ही जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन की चेतावनी दी।



जैसे समर्पण और निष्ठा हर भक्त में होनी चाहिए। पूज्य महाराज श्री की अमृतवाणी से समस्त श्रद्धालु भावविभोर हो उठे और पूरा पंडाल जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। उन्होंने यह भी कहा कि हनुमान जी पंचप्राण के रक्षक हैं - उन्होंने सुग्रीव और समस्त वानर-भालू सेनाओं के प्राणों की रक्षा की। इस अवसर पर पूर्वांचल सहप्रधान पारुल सावू, कोलकाता प्रदेश प्रचर-प्रसन्न मंत्री सुशीला बागड़ी, अंचल के अध्यक्ष सहित कई बहनों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। प्रसाद यजमान के रूप में सुनीता प्रह्लाद राठी, रेनु मल्ल, आशा सुशील चांदक, प्रमिला बिहारी की भूमिका सराहनीय रही। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्वागत समिति की सदस्याएं शोभा दामनी, निशा लड्डा, संतोष पेड़ियाल, मोहिनी गडुनी, सुशीला बाजज एवं संगीता लडा भी सक्रिय रूप से सहभागी रहीं।

सावन में हावड़ा में पंचदिवसीय हनुमंत कथा से रामभक्ति में डूबा माहौल

हावड़ा, समाज्ञ : माहेश्वरी महिला संगठन, हावड़ा की ओर से पावन सावन मास के अवसर पर आयोजित पंचदिवसीय हनुमंत कथा के तृतीय दिवस पर धार्मिक उत्साह और भक्ति भाव से पूरा वातावरण राममय हो गया। कथा का शुभारंभ प्रतिदिन की भांति प्रातः 8 से 10 बजे तक मंत्रोच्चारण एवं वेदी पूजन के साथ हुआ। पूजन में मुख्य यजमान मनमोहन-निर्मला मल्ल, किशोर-मीना राठी, राम गोपाल-कांता मर्दा, प्रकाश-कुसुम मुंदड़ा तथा सह यजमान जगन्नाथ-कंचन भट्ट, सुरेंद्र-मंजु मुंदड़ा, रजत-वंदना कारुणिका शामिल रहे। दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक की कथा में परम पूज्य महंत श्री भरत शरण जी महाराज (रामायण वृंदावन) ने भाकों को हनुमान जी की अद्भुत भक्ति और सेवा भाव की प्रेरणादायक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि जब हनुमान जी का प्रभु श्रीराम से मिलन



जैसे समर्पण और निष्ठा हर भक्त में होनी चाहिए। पूज्य महाराज श्री की अमृतवाणी से समस्त श्रद्धालु भावविभोर हो उठे और पूरा पंडाल जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। उन्होंने यह भी कहा कि हनुमान जी पंचप्राण के रक्षक हैं - उन्होंने सुग्रीव और समस्त वानर-भालू सेनाओं के प्राणों की रक्षा की। इस अवसर पर पूर्वांचल सहप्रधान पारुल सावू, कोलकाता प्रदेश प्रचर-प्रसन्न मंत्री सुशीला बागड़ी, अंचल के अध्यक्ष सहित कई बहनों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। प्रसाद यजमान के रूप में सुनीता प्रह्लाद राठी, रेनु मल्ल, आशा सुशील चांदक, प्रमिला बिहारी की भूमिका सराहनीय रही। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्वागत समिति की सदस्याएं शोभा दामनी, निशा लड्डा, संतोष पेड़ियाल, मोहिनी गडुनी, सुशीला बाजज एवं संगीता लडा भी सक्रिय रूप से सहभागी रहीं।

जैसे समर्पण और निष्ठा हर भक्त में होनी चाहिए। पूज्य महाराज श्री की अमृतवाणी से समस्त श्रद्धालु भावविभोर हो उठे और पूरा पंडाल जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। उन्होंने यह भी कहा कि हनुमान जी पंचप्राण के रक्षक हैं - उन्होंने सुग्रीव और समस्त वानर-भालू सेनाओं के प्राणों की रक्षा की। इस अवसर पर पूर्वांचल सहप्रधान पारुल सावू, कोलकाता प्रदेश प्रचर-प्रसन्न मंत्री सुशीला बागड़ी, अंचल के अध्यक्ष सहित कई बहनों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। प्रसाद यजमान के रूप में सुनीता प्रह्लाद राठी, रेनु मल्ल, आशा सुशील चांदक, प्रमिला बिहारी की भूमिका सराहनीय रही। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्वागत समिति की सदस्याएं शोभा दामनी, निशा लड्डा, संतोष पेड़ियाल, मोहिनी गडुनी, सुशीला बाजज एवं संगीता लडा भी सक्रिय रूप से सहभागी रहीं।

विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के अवसर पर फिक्की द्वारा 'एमप्लॉयमेंट थ्रू स्किल्स' के चौथे संस्करण का आयोजन



कोलकाता, समाज्ञ : फिक्की पश्चिम बंगाल स्टेट काउंसिल ने आज कोलकाता में विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के अवसर पर अपनी प्रमुख पहल 'एमप्लॉयमेंट थ्रू स्किल्स' शोपिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क इन द एरा ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज' के चौथे संस्करण का आयोजन किया। इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र के विषय 'युवा सशक्तिकरण एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से' के अनुरूप, इस सत्र में एआई-सक्षम उद्योग तत्परता पर प्रकाश डाला गया। इसमें भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण हेतु नई संभावनाओं और आवश्यक्तों को शोधित आवश्यकताओं की चर्चा की गई। पैनल चर्चा में कई उद्योग प्रमुख और विशेषज्ञ शामिल हुए, जिनमें तामोजय सेनगुप्त, मार्केटिंग डायरेक्टर, बीटी; मानोशी राय चौधरी, को-चेयरपर्सन, टेको इंडिया ग्रुप; अनीश चक्रवर्ती, चेयरमैन, सीकॉम सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी एवं सीकॉम ग्रुप; और कल्याण देबनाथ, सीईओ, निर्यातिका क्लिक डेवलपमेंट एकेडमी शामिल थे। कार्यक्रम का समापन फिक्की की डिटी सेक्टरटी जनरल, मौसमी धारा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इसमें 100 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया, जिनमें उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षा विशेषज्ञ, प्रौद्योगिकी कंपनियों, प्रशिक्षण और कौशल विकास संस्थान शामिल थे।

मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा... 'हार के डर से वापस मत आओ, पलटवार करो'

हुगली, समाज्ञ

अभिनेता से भाजपा नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने शुक्रवार को राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर पलटवार करें। इस दिन, दौलतपुर स्थित भाजपा के हुगली जिला कार्यालय में एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पीटे जाने के डर के साथ युद्ध के मैदान में नहीं उतर सकता। उन्होंने कहा कि मार खाने के बाद घर वापस मत लौटिए, यदि आवश्यक हो तो पलटवार कीजिए। आप पीटे जाने के डर के साथ युद्ध के मैदान में नहीं उतर सकते। चक्रवर्ती ने कहा कि आप पीछे खड़े होकर जंग नहीं जीत सकते। आपको निडर होकर मैदान में उतरना होगा। दिग्गज अभिनेता ने जमीनी स्तर पर सक्रियता की जरूरत



पर जोर दिया और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्रों में जमीन तुणमूल कांग्रेस सरकार महिलाओं को बुनियादी सुखा प्रदान करने में विफल रही है और प्रश्नवाच से प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता और हमारे कार्यकर्ता जवाबी कार्रवाई करें।

भू शिकायत है, तो मुझे सीधे बताएं। चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि तुणमूल कांग्रेस सरकार महिलाओं को बुनियादी सुखा प्रदान करने में विफल रही है और प्रश्नवाच से प्रसन्न है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जनता और हमारे कार्यकर्ता जवाबी कार्रवाई करें।

हावड़ा अदालत को मिली नई सात मंजिला इमारत, मुख्य न्यायाधीश ने किया उद्घाटन

हावड़ा, समाज्ञ : हावड़ा जिला अदालत को अब एक नई सात मंजिला इमारत की सुविधा मिल गई है। शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणगम ने इस अत्याधुनिक भवन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस भवन में अब से न्यायिक कार्यवाही संचालित की जाएगी, जिससे न्यायाधीशों, वकीलों और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इस उद्घाटन समारोह में कोलकाता हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश रविकृष्ण कर्पूर और शम्पा दत्ता, पश्चिम बंगाल सरकार के विधि मंत्री मलय घटक, हावड़ा की जिलाधिकारी पी. दीप प्रिया और पुलिस आयुक्त प्रवीन कुमार त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। मुख्य न्यायाधीश ने



इस अवसर पर राज्य सरकार को इस परियोजना में दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि शीघ्र ही इसी परिसर में एक और भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने बताया कि इन दोनों भवनों को जोड़कर एक संपूर्ण न्यायालय परिसर का निर्माण किया जाएगा, जिससे न्यायिक प्रणाली

विधि मंत्री मलय घटक ने कहा कि तुणमूल सरकार के कार्यकाल में राज्यभर में कई नए अदालत भवनों का निर्माण हुआ है और पुराने भवनों का नवीनीकरण भी कराया गया है, ताकि जनता को न्याय की सुलभ व्यवस्था मिल सके।

इस मौके पर जिला जज अभिजीत सोम भी मंच पर उपस्थित थे। मुख्य न्यायाधीश ने लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को सुलझाने की दिशा में भी पहल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि जिला जज और बार के सदस्य सहयोग करें तो लंबित मामलों को स्थानांतरित कर लोक अदालतों के जरिये निपटारा संभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रयास पूरी तरह स्वैच्छिक होगा लेकिन इसकी शुरुआत की जा सकती है।

हावड़ा की मशहूर गायिका मौमिता देबनाथ की मौत में हत्या की आशंका

हावड़ा, समाज्ञ : हावड़ा ग्रामीण क्षेत्र की लोकप्रिय गायिका मौमिता देबनाथ की सड़क दुर्घटना में हुई मौत अब रहस्यमय बन गई है। गुरुवार शाम को मौमिता एक सिविक वॉलंटियर की बाइक पर बैठकर पनियारा से निमदिधी जा रही थीं, तभी बेलतला क्षेत्र में एक बस ने पीछे से उनको टक्कर मारी। टक्कर लगते ही बाइक फ्लॉप हुई और दोनों सड़क पर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि बस के पिछले पहिए के नीचे आकर मौमिता की मौत हो गई और वॉलंटियर को मामूली चोटें आईं। वहीं, मौमिता की मां रूपा देबनाथ का आरोप है कि यह एक सुनिश्चित हत्या है। उन्होंने पणायुर थाने में एक सिविक वॉलंटियर और हावड़ा ग्रामीण पुलिस के एसएसआई के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज



की है। मां का दावा है कि एसएसआई से मौमिता का प्रेम संबंध था, मार्च 2015 में शादी तय थी, लेकिन उसका व्यवहार ठीक न लगने के कारण रिश्ता तोड़ दिया गया। इसके बाद से मौमिता को धमकियां मिल रही थीं, यहां तक कि 23 जुलाई को उस एसएसआई ने घर आकर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि हत्या और दुर्घटना दोनों मामलों की जांच जारी है, हालांकि प्रारंभिक जांच में दुर्घटना की संभावना जतायी जा रही है।

अलीपुर चिड़ियाघर में जानवरों की गणना पर केंद्रीय दल ने जताई संतोष

पक्षियों की गिनती अभी बाकी, दस्तावेजों की भी हो रही जांच

कोलकाता, समाज्ञ : कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में जानवरों की गणना को लेकर गडबडी के आरोप सामने आने के बाद गुरुवार को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की एक टीम निरीक्षण के लिए पहुंची। टीम ने चिड़ियाघर के विभिन्न पिंजरों और पशु अस्पताल का दौरा कर जानवरों की प्रत्यक्ष गणना की। पहले दिन स्तनधारी और सरीसृप प्रजातियों की गिनती की गई, जिसमें प्राप्त आंकड़ों से केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल संतुष्ट नजर आया। सूत्रों के अनुसार, इन वर्गों में जानवरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है, जबकि पक्षियों की गणना का कार्य अब भी बाकी है। इस निरीक्षण दल में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण,



वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक-एक प्रतिनिधि शामिल थे। चिड़ियाघर के निदेशक अरुण मुखर्जी ने टीम को सहयोग में पशु गणना से जुड़े दस्तावेजों में कथित वििसंगतियों को लेकर सवाल उठे थे। इसी संदर्भ में यह केंद्रीय जांच दल चिड़ियाघर पहुंचा है। पक्षियों की गिनती पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

भर्ती जानवरों की स्थिति और संख्या का भी ब्यूरो तैयार किया गया। गणना प्रक्रिया में पूर्व निदेशक आशिष समंत को भी आमंत्रित किया गया था। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय टीम ने न केवल वर्तमान पशु-पक्षियों से जुड़ी फाइलें, बल्कि पिछले वर्षों की जानकारी और रिकॉर्ड भी मांगे हैं, ताकि किसी भी संभावित अनियमितता की गहराई के लिए जांच हो सके। गौरतलब है कि हाल ही में अलीपुर चिड़ियाघर में पशु गणना से जुड़े दस्तावेजों में कथित वििसंगतियों को लेकर सवाल उठे थे। इसी संदर्भ में यह केंद्रीय जांच दल चिड़ियाघर पहुंचा है। पक्षियों की गिनती पूरी होने के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

समर्पण ट्रस्ट का सम्मान समारोह 29 जुलाई को समाज सेवा एवं समाज निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियां होंगी सम्मानित

कोलकाता, समाज्ञ : समर्पण ट्रस्ट द्वारा आयोजित 'समर्पण ट्रस्ट सम्मान समारोह' आगामी 29 जुलाई को भव्य रूप से संपन्न होगा। यह आयोजन होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल, कोलकाता में सायं 4:30 बजे से आरंभ होगा। इस सम्मान समारोह में समाज सेवा, दानशीलता, प्राकृतिक चिकित्सा, स्त्री सशक्तिकरण एवं समाज निर्माण जैसे विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को समर्पण समाज गौरव सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। सम्मान प्राप्त करने वाली प्रमुख विभूतियों में सजज बंसल (भामा जी शाह समर्पण समाज संस्था) और सजज संतोष के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु, डॉ. लक्ष्मण पट्टे (आचार्य लक्ष्मणा जी शर्मा प्राकृतिक चिकित्सा समर्पण समाज गौरव सम्मान - प्राकृतिक चिकित्सा



में समर्पित सेवा के लिए), रामानंद रूस्तगी (पुष्करलाल जी केडिया समर्पण समाज गौरव सम्मान - महिला सशक्तिकरण हेतु अनवरत प्रयासों के लिए) शामिल है। संवाददाता सम्मेलन में ट्रस्ट के सभापति दिनेश बजाज, ट्रस्ट के महासचिव प्रदीप ठेडिया पंज बहालटिया, मनीष बजाज, गणेश अग्रवाल एवं संजय जैन उपस्थित थे।

मूंडड़ा (सेठ सूजमल जालान समर्पण समाज गौरव सम्मान - महिला सशक्तिकरण हेतु अनवरत प्रयासों के लिए) शामिल है। संवाददाता सम्मेलन में ट्रस्ट के सभापति दिनेश बजाज, ट्रस्ट के महासचिव प्रदीप ठेडिया पंज बहालटिया, मनीष बजाज, गणेश अग्रवाल एवं संजय जैन उपस्थित थे।

न्यूज़ इन ब्रीफ

गुरुग्राम में आठ अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हिरासत में लिये गए, निर्वासित किए जाएंगे

गुरुग्राम : अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए चलाये जा रहे एक अभियान के तहत आठ बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें उनके देश वापस भेजा जाएगा। यह जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी। पुलिस ने बताया कि इन लोगों के पास से कुछ भारतीय और बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं। अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत, पुलिस धौलपुर, कामागारों, रेहड़ी-पट्टी वालों, किरायेदारों और झुग्गी-झोपड़ियों व निर्माण स्थलों पर रहने वाले लोगों की पहचान की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे आठ बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है और उन्हें विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बांग्लादेशी पहचान पत्रों के अलावा, उनके पास से कुछ भारतीय दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

नासिक सिंहरथ 2027 के लिए रेलवे की तैयारी शुरू, 5 स्टेशनों पर 1011 करोड़ खर्च होंगे

नासिक सिंहरथ 2027 में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नासिक और आसपास के 5 प्रमुख स्टेशनों पर तैयारी शुरू कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री रवीन्द्र सिंह बिट्टू ने योजनाओं की समीक्षा की। नासिक रोड, देवलाली, ओहा, खेवाड़ी और कुम्बहे सुकेणे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और दांचों के विकास पर 1,011 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म विस्तार, नए फुटओवर ब्रिज, स्टैब्लिंग लाइन, शौचालय, पानी टैंकियां, सूचना बोर्ड और होल्डिंग एरिया जैसे काम किए जाएंगे। सिंहरथ में अनुमानित 3 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए देश भर से विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। रेलवे भीड़ प्रबंधन के लिए एआई आधारित निगरानी सिस्टम और कंट्रोल रूम भी बनाएगा।

सीजीएसटी लुधियाना ने 260 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग घोटाले का बांडाफोड़ किया, दो गिरफ्तार

चंडीगढ़ : लुधियाना के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्तलय के अधिकारियों ने मंडी गोबिंदगढ़ में कई स्थानों पर छापेमारी कर फर्जी बिलिंग घोटाले में लिप्त एक गिरोह का बांडाफोड़ किया। यह गिरोह लौह और इस्पात क्षेत्र में पांच कंपनियों के जरिये फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने और पास करने में लिप्त था। मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में स्थित है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को कहा गया कि तलाशी अभियान के दौरान अधिकारियों ने एक ऐसी कार्यवाही का पर्दाफास किया, जिसमें धोखाधड़ी करने वाले लोगों द्वारा कर में डूबी रोलिंग मिलों को खरीदा जाता था और उन्हें फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) प्राप्त करने व पास करने के लिए मुखांडे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ताकि जीएसटी प्रबन्धन एजेंसियों की निगरानी से बचा जा सके। छापेमारी के बाद 24 जुलाई को इन कंपनियों का संचालन करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

पाकिस्तान से आए 185 शरणार्थियों को गुजरात में भारतीय नागरिकता प्रदान की गई

राजकोट : गुजरात के विभिन्न हिस्सों में रह रहे पाकिस्तान के 185 शरणार्थियों को शुक्रवार को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। राज्य सरकार ने यह जानकारी दी। राज्य के कच्छ, मोरवी और राजकोट जिलों में रहने वाले इन शरणार्थियों को एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी शामिल हुए। सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित इन 185 लोगों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत नागरिकता प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध जैसे अल्पसंख्यक समुदायों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वे कल्पना से परे हैं।

भारत-मालदीव संबंधों की जड़ें सागर जितनी गहरी: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुद्दुजू ने मालदीव के रक्षा मंत्रालय भवन का उद्घाटन किया

भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने की घोषणा की



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत को मालदीव का "सबसे भरोसेमंद" मित्र होने पर गर्व है। दो

के साथ व्यापार, रक्षा और समुद्री सुरक्षा समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए व्यापक वार्ता की। दोनों पक्षों ने मत्स्य पालन और कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यूपीआई, भारतीय फार्माकोपिया और द्वीप राष्ट्र को भारत की रियायती ऋण सुविधा के क्षेत्र में छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मोदी ने अपने मालदीव वक्तव्य में कहा, "हमारे लिए सदैव मित्रता सर्वप्रथम है।" उन्होंने कहा, "हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी

किसी लड़की के साथ महज दोस्ती पुरुष को सहमति के बिना यौन संबंध बनाने का अधिकार नहीं देती: अदालत

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी लड़की के साथ महज दोस्ती किसी पुरुष को उसके सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाने का अधिकार नहीं देती। अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति गिरीश कृष्णपालिया ने लड़की के साथ सहमति से संबंध बनाने के व्यक्ति के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि नाबालिग के मामले में सहमति भी वैध नहीं मानी जाती है। अदालत ने 24 जुलाई के आदेश में कहा, "सिर्फ इसलिए कि एक लड़की किसी लड़के से दोस्ती करती है, लड़के को उसकी सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाने

का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके अलावा, मौजूदा मामले में सहमति भी विधिमत्त नहीं होगी क्योंकि लड़की नाबालिग थी।" अदालत ने प्राथमिकी में पीड़िता के विशिष्ट आरोपों और उसके विरोध के बावजूद उक्त व्यक्ति द्वारा बार-बार यौन उत्पीड़न किए जाने के बारे में उसकी गवाही को रेखांकित किया। आदेश में कहा गया है, "मैं इसे सिर्फ इसलिए सहमति से संबंध बनाने का मामला नहीं मान रहा क्योंकि प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा है कि आरोपी/याचिकाकर्ता ने अपनी मोटी-मोटी बातों से उससे दोस्ती की।" न्यायाधीश ने कहा कि यह आरोपी को जमानत देने का उपयुक्त मामला नहीं है।

करीब 89 प्रतिशत रेल टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं : रेल मंत्री

नयी दिल्ली : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि रेल यात्री ऑनलाइन या कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) काउंटेंटों के माध्यम से आरक्षित टिकट बुक कर सकते हैं और करीब 89 प्रतिशत टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। उन्होंने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा डिजिटल आरक्षण और करोड़ों संदिग्ध आईडी को निष्क्रिय करने से संबंधित हालिया पहल के बारे में पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। वैष्णव ने कहा, "टिकट बुकिंग प्रणाली में गड़बड़ियों को रोकने के लिए आईआरसीटीसी

ने हाल ही में 2.5 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता आईडी को निष्क्रिय कर दिया है, क्योंकि व्यापक डेटा विश्लेषण के दौरान उन्हें संदिग्ध पाया गया।" उन्होंने कहा, "भारतीय रेलवे में, आरक्षित सीटों की मांग का पैटर्न पूरे वर्ष एक जैसा नहीं रहता और यह समय-समय पर बदलता रहता है। लोकप्रिय मार्गों और सुविधाजनक समय पर चलने वाली ट्रेनों में आम तौर पर अधिक भीड़ होती है। हालांकि, अन्य ट्रेनों में सीटें आम तौर पर उपलब्ध होती हैं। वैष्णव ने यात्रियों को कार्यक्रम टिकट मुद्देया कराने के लिए लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी।

जाति जनगणना नहीं करवा पाना मेरी गलती, अब इसे सुधारने के प्रयास कर रहा हूँ: राहुल

नयी दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान जाति जनगणना नहीं करवा पाना उनकी गलती है, लेकिन अब उन्होंने इस गलती को सुधारने के लिए कदम बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि जाति जनगणना का मुद्दा "राजनीतिक मुक़द्द" है जिसने देश की राजनीतिक जमीन को हिलाकर रख दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष उन्होंने यहां कांग्रेस के 'ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा, "मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूँ। जब मैं अपना मूल्यांकन करता हूँ तो पाता हूँ कि कहीं अच्छा काम किया तो कहीं कमी भी रह गई...आदिवासियों, दलितों और



अल्पसंख्यकों की बात हो, मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। मजिदालों के मुद्दे पर मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक बात स्पष्ट दिखती है कि एक चीज में कमी रह गई थी। यह एक गलती मैंने की, वह यह है कि ओबीसी वर्ग (के हितों

की) रक्षा जिस तरह से करनी थी, वो मैंने नहीं की। इसका कारण यह है कि आपके मुद्दे मुझे उस समय गहराई से समझ नहीं आए थे।" कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, "दलितों की कठिनाइयों को समझना आसान है...आदिवासियों के मुद्दे भी आसान से समझ आ जाते हैं। लेकिन ओबीसी की मुश्किलें या मुद्दे आसान से नहीं दिखते। मुझे अपेक्षाएं यह है कि अगर मुझे आपके इतिहास और मुद्दों के बारे में ज्यादा मालूम होता तो मैं उसी वक्त (कांग्रेस के सत्ता में रहते) जाति जनगणना करा देता। वो समय निष्कल गया। लेकिन मेरी गलती है। ...यह कांग्रेस की गलती नहीं, मेरी गलती है।"

उदयपुर फाइलस : केंद्र की मंजूरी के विरुद्ध उच्च न्यायालय को सुनवाई करने का दिया गया निर्देश

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह फिल्म 'उदयपुर फाइलस - कन्हैया लाल टेलर मर्डर' की रिलीज को लेकर केंद्र सरकार की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 28 जुलाई को सुनवाई करे। न्यायमूर्ति सुर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ ने कहा कि फिल्म रिलीज पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली फिल्म निर्माताओं की अपील निरर्थक है, क्योंकि उन्होंने केंद्र के 21 जुलाई के आदेश को स्वीकार कर लिया है जिसमें छह उग्र दृश्यों को हटाने का सुझाव देने समेत 'डिस्केलर' (अस्वीकरण) में संशोधन के साथ रिलीज को मंजूरी दी गई थी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अशरफ मदनी और कन्हैया

लाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद जावेद को केंद्र के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय को आदेश दिया गया। एक संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश हुए वकील सैयद रिजवान ने कहा कि मदनी और जावेद का यह दावा कि फिल्म में एक खास समुदाय को निशाना बनाया है और देश के सामाजिक ताने-बाने को खतरा है, "उनकी कोरी कल्पना के अलावा कुछ नहीं है।" उन्होंने कहा, "जब 'कर्मिक फाइलस' रिलीज हुईं, केरल स्टोरी रिलीज हुईं, तब कुछ नहीं हुआ। जब पहलगाम हमला हुआ, जब पुलवामा आतंकी हमला हुआ, तब देश का सामाजिक ताना-बाना प्रभावित नहीं हुआ। हमारे देश का सामाजिक ताना-बाना कहीं अधिक मजबूत है।"

भारत, पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच सीधे संपर्क के बाद सैन्य संघर्ष रोकने पर बनी थी सहमति : सरकार

नयी दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों देशों के सैन्य संचालक महानिदेशकों (डीजीएमओ) के मध्य "सीधे संपर्क" के परिणामस्वरूप 10 मई को संघर्ष विराम के लिए सहमति बनी थी तथा इस संपर्क की पहल "पाकिस्तान की ओर से की गई थी।" विदेश मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या यह सच है कि "भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पाकिस्तान के खिलाफ तीन दिन की (सैन्य) कार्रवाई के बाद अमेरिकी हस्तक्षेप के चलते हुआ था, जब संघर्ष में भारतीय सशस्त्र बलों का पलड़ा भारी था?" लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया, "हमारे सभी वार्ताकारों को एक ही संदेश दिया गया कि भारत का दृष्टिकोण -- लक्ष्य केंद्रित, संतुलित और तनाव न बढ़ाने वाला है।" मंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान, 10 मई को "दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सीधे संपर्क के परिणामस्वरूप गोलाबारी और सैन्य गतिविधि रोकने पर सहमत हुए। इस संपर्क की पहल पाकिस्तानी पक्ष द्वारा की गई थी।" उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान और पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के अपने मुख्य लक्ष्य "8 मई को ही हासिल कर लिए थे।"

इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ लगातार दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने मोदी

नयी दिल्ली : नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर लगातार सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे नेता बन गए। अभी तक सबसे अधिक समय तक इस पद पर रहने का रिकॉर्ड 24 वर्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम है। अधिकारियों ने बताया कि मोदी ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4,078 दिन पूरे कर लिए। गांधी 24 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1977 तक लगातार 4,077 दिन तक प्रधानमंत्री रही थीं। लगातार तीन बार

इस पद पर बने रहे और उनका कार्यकाल 6,130 दिन का रहा। राज्य और केंद्र में सरकार के निर्वाचित प्रमुख के रूप में मोदी पहले ही सबसे लंबे कार्यकाल को रिकॉर्ड बना चुके हैं। वह 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बने। आजादी के बाद जन्मे मोदी सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता हैं। अधिकारियों ने बताया कि मोदी केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में दो कार्यकाल पूरे करने वाले एकमात्र गैर-कांग्रेसी नेता हैं।

| सर्वाधिक समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले नेता | | |
|--|--|--|
| | | |
| इंदिरा गांधी (15.08.1947-27.05.1964) | नरेन्द्र मोदी (26.05.2014-...) | इंदिरा गांधी (24.01.1966-24.03.1977) |
| 6130 दिन | 4078 दिन | 4077 दिन |

राष्ट्रपति पद पर तीन साल : मुर्मू ने कहा, राष्ट्र की प्रगति से सबको जोड़ने का करती हूँ प्रयास

नयी दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे करने पर कहा कि वह हमेशा समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों और पिछड़े वर्गों को देश की विकास यात्रा से प्रभावी ढंग से जोड़ने का प्रयास करती हैं। कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न पहलों को शुरू करने के मौके पर अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि राष्ट्रपति भवन दिव्यांगजनों के लिए अधिक सुलभ हो गया है। मुर्मू (67) ने 25 जुलाई 2022 को 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। इसके साथ ही वह देश की



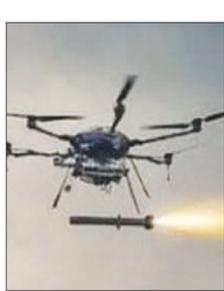
आदिवासी राष्ट्रपति बन गयी थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह संतोष की बात है कि पिछले तीन वर्षों में कई ऐसे निर्णय लिए गए और कार्य किए गए जिनसे नागरिकों का राष्ट्रपति भवन से जुड़ाव बढ़ा है। उन्होंने

कहा, "हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों और पिछड़े वर्गों को देश की विकास यात्रा से प्रभावी ढंग से जोड़ा जाए।" मुर्मू के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, "राष्ट्रपति संसदा" दिव्यांगजन-अनुकूल संसदा बन गई है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में कई नई पहल की जाएंगी। मुर्मू ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान की 50 सूत्री सिफारिशों पर कार्यान्वयन के बाद राष्ट्रपति भवन, अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय दिव्यांगजन अनुकूल परिसर बन गए हैं। मुर्मू ने

मार्च 2027 तक राष्ट्रपति भवन को 'नेट जीरो' बनाने की पहल की शुरूआत की। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट अब 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। बयान के अनुसार, राष्ट्रपति ने 250 से अधिक वस्तुओं की नीलामी के लिए 'ई-उपहार सीजन 2' की भी शुरूआत की। ई-उपहार राष्ट्रपति सचिवालय का एक नीलामी पोर्टल है जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति और भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों को भेंट किए गए उपहार और वस्तुओं की नीलामी करना है। बयान में कहा गया है कि नीलामी से प्राप्त सभी आय बच्चों के कल्याण से जुड़ी पहलों को दान की जाएगी।

डीआरडीओ ने ड्रोन से दागे जाने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया

नयी दिल्ली : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ड्रोन से दागी जाने वाली एक मिसाइल का आंध्र प्रदेश में एक परीक्षण स्थल पर सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि यह परीक्षण कुरुलम में किया गया। सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "भारत की रक्षा क्षमताओं को एक बड़ी मजबूती देते हुए, डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के कुरुलम स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज (एनओएआर) में मानवरहित यान से दागे जाने वाली सटीक मारक क्षमता



वाली मिसाइल (यूएलपीजीएम)-वी3 का सफल परीक्षण किया।" यह मिसाइल पहले डीआरडीओ द्वारा

आदिवासी अंचल को जोड़ेगा नया रेल रूट: नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद लाइन के लिए फाइनल सर्वे को मंजूरी

नई दिल्ली : आदिवासी क्षेत्रों के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने नीमच-बांसवाड़ा-दाहोद होते हुए नंदुरवार तक नई रेलवे लाइन के फाइनल सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी है। 380 किलोमीटर लंबी इस प्रस्तावित लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह लाइन दिल्ली से मुंबई के बीच एक नया, छोटा और रणनीतिक मार्ग उपलब्ध कराएगी जो दाहोद से होकर तामी सेक्शन को मुख्य दिल्ली-मुंबई रूट से जोड़ेगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के छह शहरों को सीधे लाभ पहुंचाएगी। शाहादत जैसे प्रमुख कस्बों को भी मार्ग में शामिल किए जाने की संभावना है। बांसवाड़ा, जो अब तक रेल संपर्क से वंचित था, खनिजों से भरपूर क्षेत्र है और माल ढुलाई की दृष्टि से बेहद उपयुक्त है। इस नई लाइन से न केवल माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे।

असम में अतिक्रमणकारियों में बिहार के लोग भी शामिल, उनके दावों का सत्यापन करेंगे : हिमंत

गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि बिहार जैसे राज्यों से होने का दावा करने वाले लोग पूर्वोत्तर राज्य में सरकारी, वन और अन्य भूमि पर अतिक्रमण करने वालों में शामिल हैं। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इन लोगों का विवरण उन स्थानों के प्राधिकारियों के साथ साझा करेगी, जहां से होने का ये दावा कर रहे हैं ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वे वास्तव में "सीमा पार" से तो नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने गोलाघाट जिले के उरियमघाट में अतिक्रमण रोधी अभियान के लिए स्थलों का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से कहा, "जब हमने अतिक्रमणकारियों की सूची देखी, तो पाया कि ये लोग सिर्फ असम से नहीं हैं। इनमें कछार, श्रीभूमि, धुबरी, होजई, नागांव, मोरगांव जैसे जिलों के लोग हैं, साथ ही बिहार के भी लोग हैं।" शर्मा ने कहा, "उन लोगों ने कहा है कि वे बिहार से हैं, लेकिन



वे सीमा पार से भी हो सकते हैं।" उन्होंने कहा कि इन लोगों के नाम, पते और अन्य विवरण लिए जाएंगे तथा उस स्थान के अधिकारियों के साथ साझा किए जाएंगे जहां से वे आने का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "यदि वे उस क्षेत्र के वास्तविक निवासी हैं, तो हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। परंतु वहां के स्थायी निवासी नहीं होने पर स्थानीय अधिकारी कदम उठा सकते हैं।" उन्होंने कहा कि उरियमघाट में अतिक्रमणकारियों ने सैकड़ों बीघा वन भूमि पर कब्जा कर रखा है।

महिलाओं के 'अश्लील' चित्रण के कारण अल्ट, उल्लू समेत 20 से अधिक ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया

नयी दिल्ली : सरकार ने विभिन्न कानूनों, खासकर महिलाओं के अश्लील चित्रण पर रोक से जुड़े कानून के उल्लंघन के कारण उल्लू, अल्ट और देसीफ्लिक्स समेत 20 से अधिक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया का आदेश दिया है। सूत्रों ने शुक्रवार यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि इस प्रतिबंध का उद्देश्य विशेष रूप से नाबालिगों के लिए अश्लील सामग्री की आसान उपलब्धता को रोकना तथा यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल सामग्री शालीनता व कानून की सीमाओं के अंदर रहे। सूत्रों ने बताया कि विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करने वाले ऐप में अल्ट, उल्लू, बिग शॉट्स ऐप, देसीफ्लिक्स, ब्यूमेक्स, नक्सला लाइट, गुलाब ऐप, कंगन ऐप, बुल ऐप, जलवा ऐप, वाउ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिटप्राइम, फेनेओ, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, हॉटएक्स वीआईपी, हलचल ऐप, मूडएक्स, नियोनएक्स वीआईपी, फूगी, मोजफ्लिक्स और ट्राइफ्लिक्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि वे भारत में इन वेबसाइटों तक सार्वजनिक पहुंच पर रोक लगाएं।

देशभर में 200 से अधिक 'कैंसर डे केयर सेंटर' स्थापित किए जाएंगे: सरकार

नयी दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को संसद में कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में देशभर में 200 से अधिक 'डे केयर कैंसर सेंटर' (डीसीसी) की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिनमें आंध्र प्रदेश में 14 केंद्र शामिल हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमए) के कर प्रजीकरण आंकड़े का उपयोग करके राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषण किया और केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा के अनुसार, राज्यों के परामर्श से 'डे केयर कैंसर सेंटर' की स्थापना की योजना बनाई। मंत्री ने बताया कि अधिक जोखिम वाले जिलों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने एवं दोहराव से बचने के लिए



राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) द्वारा उन्हें अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया, "वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, देश भर में 200 से अधिक डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, जिनमें आंध्र प्रदेश में 14 ऐसे केंद्र शामिल हैं।" जाधव ने संसद के निचले सदन में एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस साल 20 जुलाई तक 30 वर्ष और उससे अधिक आयु की 25.42 करोड़ महिलाओं में से 10.18 करोड़ की गर्भाशय-ग्रीवा (सर्विकल) कैंसर के लिए जांच की जा चुकी है।

शैक्षिक संस्थानों में आत्महत्याओं से निपटने के लिये शीर्ष अदालत ने देशव्यापी दिशानिर्देश जारी किए

नयी दिल्ली : शैक्षिक संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बढ़ती रोकथाम के लिए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इस समस्या से निपटने के लिए अखिल भारतीय दिशानिर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शैक्षिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों और छात्र-केंद्रित वातावरण में विद्यार्थियों की आत्महत्या पर रोकथाम के लिए एक एकीकृत, लागू करने योग्य ढांचे के संबंध में देश में 'विद्यार्थी और न्यायमूर्ति संस्था' बनी हुई है। प्रंह देशानिर्देश जारी करते हुए पीठ ने कहा कि ये उपाय तब तक लागू और बाध्यकारी बने रहेंगे, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त

दशानिर्देश शामिल है, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2023 में जारी किया गया था। इसका उद्देश्य स्कूलों विद्यार्थियों की आत्महत्या को रोकना है। न्यायालय ने कहा कि व्यापक पहुंच के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी अन्याय के उच्च छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 'मनोदर्पण' अभियान शुरू किया। यह फैसला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उच्च आदेश के विरुद्ध अपील पर आया है, जिसमें विद्यावाचनपन में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी करने वाले 17 वर्षीय अश्वर्थी की अप्राकृतिक मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी गई थी।

